



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]  
No. 25]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 1984/पौष 7, 1905  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 1984/PAUSA 7, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1984

सां० का० नि० 46 (अ).—चूंकि सड़क परिवहन  
निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 44  
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
और दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 का  
अधिक्रमण करते हुए सड़क परिवहन निगम की धारा 44 की  
उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राज-  
पत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड (i) दिसंबर 1, 1983 में  
भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन  
पक्ष) की अधिसूचना सां० का० नि० सं० 875-अ दिनांक  
दिसंबर, 1, 1983 के तहत नियमों का समूदा प्रकाशित  
किया गया था और सरकारी गजट में उक्त अधिसूचना के  
प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि के अन्दर इस अधिसूचना  
से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से अपने-अपने मुद्राव/  
आवृत्तियां भेजने का अनुरोध किया गया था ;

और चूंकि उक्त गजट सर्वसाधारण के लिए पहली  
दिसम्बर, 1983 को उपलब्ध हो गया था ;

और चूंकि जो भी मुद्राव/आवृत्तियां प्राप्त हुईं उन पर  
नियम विचार विमर्श कर लिया गया है ;

इसलिए अब सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950  
(1950 का 44) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए और दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम  
1973 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित  
नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—(1) इन नियमों को  
दिल्ली परिवहन निगम (निदेशक मंडल) नियम, 1983  
कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से  
अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से सड़क परिवहन निगम अधिनियम,  
1950 (1950 का 64) अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से दिल्ली परिवहन निगम के निदेशकों का  
बोर्ड अभिप्रेत है,

(ग) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) “निगम” से दिल्ली परिवहन निगम अभिप्रेत है,

- (ङ) "निदेशक" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है,  
 (च) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है  
 (छ) "प्रबंध निदेशक" से निगम का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है।

3. बोर्ड का गठन : बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्न-लिखित निदेशक होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) निगम का प्रबंध निदेशक,  
 (ख) पांच अधिकारी, और  
 (ग) पांच व्यक्ति जिनमें से—

- (1) एक नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी का प्रतिनिधि होगा जो उस कमिटी के सदस्यों में से ही कमिटी द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
- (2) एक दिल्ली महानगर परिषद का प्रतिनिधि होगा जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाएगा,
- (3) एक दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि होगा जो निगम द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाएगा।
- (4) दो व्यक्ति वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी।

4. कार्यकाल :—प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, को छोड़ कर एक निदेशक का कार्यकाल, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

फिर भी यह भी नियम 3 के खंड (ग) के उपखंड (1) उपखंड (2) या (3) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति यदि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी या दिल्ली महानगर परिषद या दिल्ली नगर निगम का, जैसी भी स्थिति हो, सदस्य नहीं रहता तो वह निगम के बोर्ड का निदेशक भी नहीं रहेगा।

5. आकस्मिक रिक्तियां भरना :—निगम के बोर्ड में जब कभी आकस्मिक रिक्ति होती है, तो केन्द्रीय सरकार इसे भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

6. गणपूर्ति (कोरम) निगम के बोर्ड की बैठक में कोर बनाने के लिए निदेशकों की अपेक्षित संख्या चार होगी जिनमें अध्यक्ष भी शामिल है।

7. निदेशकों को भत्ते :—नियम 3 के खंड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक, अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे और वह अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत नियुक्त बोर्ड की या बोर्ड की समितियों की (एतदपश्चात् इस नियम में जिसे समिति कहा गया है) किसी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली संघ क्षेत्र से बाहर जाता है तो वह वही टी.ए.डी.ए. प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को नियमानुसार मिलने हैं।

(2) नियम 3 के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 50/- रु० (पचास रुपए) और बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 40/- रु० (चालीस रुपए) शुल्क के रूप में प्राप्त करों का हकदार होगा।

फिर यह भी कि यदि कोई निदेशक बोर्ड की बैठक में और समिति की बैठक में एक ही दिन भाग लेता है तो वह इन बैठकों में भाग लेने के लिए केवल 50/- (पचास रुपए) पाने का ही हकदार होगा।

फिर यह भी कि ऐसे निदेशक को किसी एक महीने के दौरान शुल्क की कुल देय राशि तीन सौ रुपए से अधिक नहीं होगी।

(3) नियम 3 के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक यदि बोर्ड या समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से बाहर जाता है तो वह उन्हीं शर्तों और दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा जो ग्रेड 'ए' में उच्चतर रैंक के केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को स्वीकार्य होते हैं।

(4) यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते या दोनों ही भत्तों के विल पर, लेखा परीक्षा के लिए और भुगतान के लिए भेजने से पूर्व निदेशक प्रति हस्ताक्षर स्वयं करेगा।

8. हवाई जहाज द्वारा यात्रा :—अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक जैसी भी स्थिति हो, अपने विवेकानुसार और अन्य निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक की जैसी भी स्थिति हो, पूर्वानुमति से अधिनियम के अन्तर्गत अपना कर्तव्य निभाने के लिए हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं।

9. बोर्ड के सहयोजित व्यक्तियों को परिश्रमिक :—

(1) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बोर्ड में सहयोजित कोई व्यक्ति (एतदपश्चात् इस नियम में जिसे "सहयोजित व्यक्ति" कहा गया है) या तो अवैतनिक रूप से कार्य करेगा या परिश्रमिक के आधार पर कार्य करेगा। यह परिश्रमिक जैसा कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्धारित करें, जो प्रतिमाह 100/- रुपए या प्रतिदिन 50/- रुपए से अधिक नहीं होगा।

(2) सहयोजित व्यक्ति—

(क) यदि केन्द्रीय सरकार या कानून के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम में सेवारत है, तो वह वही यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा जो उसे सरकार या निगम के अधिकारी होने के रूप में, संबंधित नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य होता, वगैरें कि वह ये भत्ते नियोक्ता से प्राप्त नहीं करेगा।

**MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**

(Transport Wing)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 1984

G.S.R. 46 (E).—Whereas the draft rules in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950) and in supersession of Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973 published as required by sub-section (1) of section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950) and in supersession of Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973 were published as required by sub-section (1) of section 44 of the Road Transport Corporation Act, 1950 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) dated the 1st December, 1983 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) G.S.R. No. 875-E dated the 1st December, 1983 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of 30 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 1st day of December, 1983 ;

And whereas objections or suggestions received in the matter have been considered ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 44 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), and in supersession of Delhi Transport Corporations (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby makes the following rules :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Transport Corporation (Board of Directors) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) ;
- (b) "Board" means the Board of Directors of the Delhi Transport Corporation ;
- (c) "Chairman" means the Chairman of the Board ;
- (d) "Corporation" means the Delhi Transport Corporation ;
- (e) "Director" means a member of the Board ;
- (f) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Board.

(g) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation.

3. Composition of Board.—The Board shall consist of a Chairman and the following Directors to be appointed by the Central Government, namely :—

- (a) the Managing Director of the Corporation ;
- (b) five officials ; and
- (c) five persons of whom—
  - (i) one shall to be a representative of the New Delhi Municipal Committee nominated by that Committee from among the members of that Committee,
  - (ii) one shall be a representative of the Metropolitan Council of Delhi elected from among themselves by the members of that Council ;
  - (iii) one shall be a representative of the Municipal Corporation of Delhi elected from among themselves by the members of that Corporation ;
  - (v) two shall be persons nominated by the Central Government.

4. Term of office.—The term of office of a Director, other than the Managing Director or the Chairman as the case may be, shall be for a period of three years from the date of his appointment and he shall be eligible for reappointment ;

Provided that a person appointed under sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (c) of rule 3 shall cease to be a Director of the Board of the Corporation if he ceases to be a member of the New Delhi Municipal Committee or the Metropolitan Council of Delhi or the Municipal Corporation of Delhi, as the case may be.

5. Filling of casual vacancies.—Where a casual vacancy occurs in the Board of the Corporation, the Central Government may appoint a person to fill the casual vacancy.

6. Quorum.—The number of Directors necessary to constitute a quorum at a meeting of the Board of the Corporation shall be four including the Chairman.

7. Allowances to Directors.—(i) A Director appointed under clause (b) of rule 3 shall hold office in an honorary capacity and shall be governed by the rules applicable to Central Government officials for the purposes of entitlement of T.A. and D.A. for any journey performed by him outside the Union territory of Delhi for attending any meetings

of the Board or of the committees of the Board, appointed under section 12 of the Act (hereinafter referred to as the committee in this rule).

(2) Director appointed under clause (c) of rule 3 shall be entitled to a free of fifty rupees for attending each meeting of the Board and to a fee of forty rupees for attending each meeting of a committee of the Board.

Provided that where any such Director attends on the same day a meeting of the Board and a meeting of the Committee, attending such meetings:

Provided further that the aggregate amount of the fee payable to such Director during any month shall not exceed three hundred rupees.

(3) If a Director appointed under clause (c) of rule 3 performs any journey to a place outside the Union territory of Delhi for attending any of the meetings of the Board or of the committees, he shall be entitled to draw travelling and daily allowances at the scale and on the conditions admissible to a Central Government officer of the higher rank in Group A.

(4) A bill for travelling allowance or daily allowance or both shall be countersigned by the Director himself before such bill is submitted for audit and payment.

8. Travel by Air.—The Chairman or the Managing Director, as the case may be, at his discretion and other Directors with the previous permission of the Chairman or the Managing Director, as the case may be, may travel by air in discharge of their duties under the Act.

9. Remuneration to persons associated with the Board.—(1) A person associated with the Board under Section 10 of the Act (hereinafter in this rule referred to as "the associated person") may either work in an honorary capacity or be paid such remuneration, not exceeding one thousand rupees per mensem, or fifty rupees per diem, as the Board may, with the approval of the Central Government, determine.

(2) The associated person—

- (a) if he is in the service of the Central Govt. or of any Corporation established by law, shall be entitled to draw such travelling and daily allowances as may be admissible to him under the rules governing him as a servant of that Government or such Corporation subject to the conditions that he shall not draw such allowances from his principal employer.

[F. No. TGD(27/83)]

G. J. MISRA, Jt. Secy.